



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५९] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च २१, १९७८/फाल्गुन ३०, १८९९
No. ५९] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 1978/PHALGUNA 30, 1899

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संलग्न वी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के लिए
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्षिक भवान

नियास: व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. १६-इ०. टी. सी.(पी. एन.)/७८

नई दिल्ली, २१ मार्च, १९७८

विषय : इमारती लकड़ी का नियर्ति

मिसिस्ल सं. ६/१९/७८/इ०. आई.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. ३३-
इ०. टी. सी.(पी. एन.)/७७ दिनांक ८ दिसम्बर, १९७७ की ओर ध्यान आकर्ष किया
जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर सत्वार छात्र आगे यह निश्चय किया गया है कि पुर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में निरीदृष्ट इमारती लकड़ी के नियर्यत के लिए नीति में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया जाए :—

(i) कंपनिकारों की वह सी पंक्ति में प्रदर्शित “स्लीपर और रेलवे स्लीकड़ी” का गठन दूर किया जाए।

(ii) अतिरिक्त कंपनिकारों के दस प्रकार पहा जाए :

“कंपनिकारों से बहुत में निरीदृष्ट पलंगकों के होते हुए में, इमारती लेकड़ी के किसी भी प्रकार के स्लीपर की नियर्यत की अनुमति रेलवे द्वारा स्वीकृत की गई सीमा और किसी के अतिरिक्त नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात आवेदनपत्रों पर “प्राप्ति के आधार पर” विचार किया जाएगा।”

का. वे. शशांक, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियर्यत

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 16-ETC(PN)/78

New Delhi, the 21st March, 1978

Subject : Export of Timber.

P. No. 6/19/76/EL.—Attention is invited to Public Notice No. 33-ETC (PN)/77 dated the 6th December, 1977, on the above subject.

2. On review of the position it has further been decided by Government to amend the policy for export of Timber as contained in the aforesaid Public Notice, as under :—

(i) The word “Sleepers and” appearing in first line of paragraph 4 stands deleted; and

(ii) Additional paragraph 16 may be read as under :—

“Notwithstanding the provisions contained in paragraphs 1 to 15, export of sleepers of any species of timber shall not be allowed except to the extent and for the species which Railways agree to. Applications will be considered “on merits”, thereafter.”

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports